the Chief Minister of Madhya Pradesh is a matter of great indignation and shame.

If custodians of law and order commit such heinous crimes and get away with it then criminals can easily have a free hand.

It has been alleged that many women were detained for 18 days at the police camp and even 'paraded naked' in a nearby village, If this is true, then the suspicion that there is a presence of some criminals in the police force gets credence.

The attitude of the Police high ups was exposed when the Police Commissioner of Delhi justified the treatment of Maya Tyagi on the ground that dacoits deserved no better treatment. If the highest authority in the Police Department holds such views then there is no wonder that the Constables and persons in lower rank can behave in any manner they feel like.

Failure on the part of the Government to take action against Police, as has happened in the case of Maya Tyagi or housewives of textile workers at Modinagar, would lead to the feeling among Police that the Government was willing to connivenance at Police atrocities against women.

I request the Government to take immediate and firm action against the guilty ones so that it may act as a deterrent in future.

(x) ALLEGED UN-HYGIENIC CONDITIONS PREVAILING AT SHEIKHPURA RAILWAY STATION IN BIHAR.

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : उपाष्पक्ष महोदय, शेखपुरा रेलवे स्टेशन, जिला मुगेर बिहार बहुत ही दयनीय स्थिति में है, जहां विश्राम धर है वहीं पर एक खुला हुआ शौचालय है जो स्वास्थ्य के दृष्टि-कोएा से बीमारी का घर है। गंदगी का संवार चारों भोर लगा रहता है। सारे समय यात्रियों को मल-मूत्र के बीच ही रहना पड़ता है। शेखपुरा मुंगेर जिला में एक महत्वपूर्ण स्थान है। रेल मंत्रालय का भ्यान इस स्रोर आकृष्ट करती हूँ कि द्वितीय श्रोणी के प्रतीक्षालय स्थित शौचालय को भ्रन्यत्र हटाया जाए एवं साथ ही साथ स्टेशन के बाहर की गंदगी को समाप्त करने के लिए बाउंड्री वाल (दीवाल) का निर्माण किया जाए। नहीं तो सैकड़ों लोगों को महामारी का शिकार होना पड़ेगा।

(xi) Steps to Improve the lot of beggars by providing them with Jobs.

श्री रामलाल राही (मिसरिख): उपाघ्या महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के 33 वर्षों
से ग्रधिक की ग्रवधि बीत जाने पर भी ग्राज
भी देश के लाखों व्यक्ति भिक्षावृत्ति पर
ग्रपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। रेलवे
स्टेशनों, बस स्टापों ग्रौर बड़े तथा छोटे
शहरों में उनकी संख्या को देखकर प्रत्येक
व्यक्ति ग्रातंकित हो जाता है। जब भी हम
किसी विदेशी प्रयंटक को चित्रड़ों में लिपटे
भारतीय भिखारियों से घरा देखते हैं तभी
हमारी 34 वर्षों के तथाकथित सामाजिक
तथा ग्राधिक विकास की वास्तविकता नग्न
रूप में सामने ग्रा जाती है ग्रौर हमारा सिर
शमं से भुक जाता है।

सरकार को चाहिए कि वह इन लाखों व्यक्तियों को, जिन्होंने भिक्षावृत्ति को अपनाया है, सहायता प्रदान करे, ताकि ये लोग सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें और देश के अच्छे नागरिक बन सकें। भिक्षा की विभीषिका को समाप्त करने के उपाय किए जाने चाहिए। जब तक सरकार इस जन-शक्ति को उद्योगों तथा अन्य व्यवसायों में नियोजित करने की एक निश्चित

योजना नहीं बनाती, तब तक यह विभी-विका और अधिक मीषण होती जाएगी भीर भारत की प्रतिष्ठा कम होती जाएगी।

सरकार का यह कर्तं व्य है कि वह समाज के इस वर्गं को, जोकि भिक्षावृत्ति में लगे हैं तथा पशुबत जीवन व्यतीत कर रहे हैं और प्राधिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दिष्ट से पिछड़े हुए हैं, सम्माननीय जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करने में तथा प्राणामी पीढ़ियों को इस विभीषिका से बचाने के लिए उपाय करे और इस संबंध में कानून भी बनाए।

MR. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, we go to the next item, Items 11 & 12. The time alloted is two hrs. We have already spent more than one and a half hours. There are about two or three speakers, two from the opposition and one from the ruling party. I would request each Hon. Member not take more than three to four minutes. We have got to complete the Bill by 3-30. Now, I call Shrimati Pramila Dandavate.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): This is second reading.

MR. DEPUTY SPEAKER: I know you will all co-operate. I know. Mr. Ramavatar Shastri is my friend, always.

CINE-WORKERS WELFARE CESS BILL

AND

CINE-WORKERS WELFARE FUND BILL (Contd.)

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य): उपाध्यक्ष महोदय, मैं वसंत साठे जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। रोज-रोज हमारी भ्रोर सें ग्रालोचना सुनते हैं, हमें करनी पड़ती है—श्राज इन्होंने घन्यवाद देने का मौका दिया है। सौ फीसदी घन्यवाद तो नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी यह जो प्रयास है, इसके लिए वे घन्यवाद के पात्र हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में एंक करोड़, 25 लाख लोग रोजाना पिक्चर देखते हैं। इतना प्रभावशाली माध्यम है। अगर सरकार चाहती तो इसके जरिए समाज में पूरा परिवर्तन कर सकती थी।

जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं, एक नया समाज बनाना चाहते हैं, शोषण विहीन समाज बनाना चाहते हैं श्रीर उसके श्रनुरूप लोक घारएगा, मानसिक घारएगा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फिल्में सर्वोत्तम माध्यम सिद्ध हो सकती हैं। कोई ग्रीर इतना ग्रधिक प्रभावशाली माध्यम इसके लिए ग्रापको नहीं मिल सकता है सिवाय फिल्मों के। नेशनल इंटीग्रेशन लाने में भी फिल्में बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। हम देखते हैं कि दक्षिण के लोगों में जहां हिन्दी का विरोध हम्रा करता था वहां पर भाज हिन्दी पिक्चजं बहत पापूलर हो रही हैं। हिन्दी पिक्चर्ज की कापियां भी वहां बनने लगी हैं। इसका साफ मतलब है कि फिल्में विहीकल फार नेशनल इंटीग्रेशन भी हो सकती हैं। इस माध्यम के बारे में इतने सालों के बाद जो श्राप सोचने का काम कर रहे हैं यह अच्छा काम है भीर इसके लिए म्राप बधाई के पात्र हैं।

हमारे देश में सुन्दर-सुन्दर पिक्च अंभी बनती हैं भौर गन्दी भी बनती हैं। कहा जाता है कि समाज में जो काइम बढ़ रहे हैं उसके लिए भी फिल्म इन्डस्ट्री बहुत हद तक जिम्मेदार है। ऐसा सोशल थिक्ज का विचार है ग्रीर इसरे लोगों का भी विचार